

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50

संख्या: 279

प्रभात

कोटा, बुधवार 23 जुलाई, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

भाजपा सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी?

इस संभावना से आतंकित जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया और जब भाजपा हाईकमान त्याग पर कार्यवाही नहीं कर रहा था तो धनखड़ ने इस्तीफे की खबर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जुलाई। क्या मोदी सरकार बिखर रही है? क्या नेताओं का असंतोष मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहचान बनता जा रहा है, क्योंकि वे हर घटनाक्रम के कथानक पर नियन्त्रण करने की कोशिश तथा सिर्फ अपनी बात मनवाने और “यस सर” कहने वाली संस्कृति को सुनिश्चत कर रहे हैं?

जगदीप धनखड़ का इस्तीफ़ा और उससे जुड़े तमाम विवादों से यह साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार का स्पष्ट और सीधा संदेश है – इस सरकार में सिर्फ़ हाँ में हाँ मिलाने वालों के लिए ही जगह है।

चाहे उपराष्ट्रपति से इस्तीफ़ा मांगा गया हो या उन्होंने खुद संकेत समझकर इस्तीफ़ा दिया हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों का नतीजा एक ही है – प्रधानमंत्री और उनकी टीम की साख़ को बड़ा झटका लगा है।

खबर है कि सरकार उपराष्ट्रपति और

- **वैसे भी धनखड़ आरएसएस के नज़दीक माने जाते हैं तथा संघ के दबाव में ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल।**
- **कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्र.मंत्री नरेंद्र मोदी के तनाव की स्थिति की भी कुछ छाया तो नहीं है, धनखड़ प्रकरण पर।**
- **इसके अलावा, हाल ही में अपनी कोटा यात्रा के दौरान, धनखड़ ने काफी तीखी आलोचना की थी, कोटा की कोचिंग क्लाॅसेज़ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर भारी आपत्ति की थी, क्योंकि अधिकतर कोचिंग इन्स्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक ओम बिड़ला के नज़दीक के लोग बताये जाते हैं। ओम बिड़ला ने अपनी भावनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।**
- **कई सवाल अनुत्तरित हैं, इस प्रकरण में, जिनका जवाब आना अभी बाकी है।**

राज्यसभा के सभापति के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर

रही थी।

दोपहर बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ

मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। राजनाथ सिंह से भाजपा सांसदों को फोन करके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने को कहा गया। कुछ मनोनीत सांसदों को भी बुलाया गया और सभी से इस बात को गोपनीय रखने को कहा गया। धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर पहल वही करे। बताया गया है कि उन्होंने इस बारे में नेतृत्व को सूचित नहीं किया। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बहस की भी अनुमति दे दी, जिससे विपक्ष को विभिन्न प्रकार के सवाल पूछने का मौका मिला, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। यह वही मुद्दा था, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ सीमित बातचीत ही हुई थी। धनखड़ को लगने लगा था कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में 7 नये न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी

जयपुर, 22 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट को सात नए न्यायाधीश और मिल गए हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सात नए न्यायाधीशों में से छह अधिवक्ता कोर्टे से और एक न्यायिक अधिकारी कोर्टे से जज बने हैं। वकील

- **आशा की जा रही है कि राजस्थान हाई कोर्ट के काम की रफ्तार में तेजी आयेगी। अभी हाई कोर्ट में करीब 6 लाख साठ हजार मुकदमे लम्बित हैं।**

कोर्टे से जज बनने वाले संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघी हैं, जबकि न्यायिक अधिकारी कोर्टे से संगीता शर्मा को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय विभाग ने इस संबंध में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। संदीप तनेजा को हाईकोर्ट का स्थाई जज और शेष छह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मिग-21 की भारतीय वायु सेना से विदाई होगी

नई दिल्ली, 22 जुलाई। भारतीय वायु सेना रूस निर्मित मिग-21 लड़ाकू विमानों को संतबर में सेवानिवृत्त कर देगी। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना को सेवा देने के बाद मिग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में विदाई दी जाएगी।

मिग-21 को 1963 में वायु सेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया है। मिग-21 एक हल्का सिंगल पायलट फाइटर जेट है। सोवियत रूस के मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे

- **सूत्रों ने बताया कि 62 साल वायु सेना में सक्रिय रहे इन विमानों को चंडीगढ़ एयर बेस पर एक समारोह में विदाई दी जाएगी।**

1959 में बनाना शुरू किया था। यह विमान 18 हजार मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये एअर टू एयर मिसाइलों और बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है।

इसकी स्पीड अधिकतम 2,230 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1,204 नॉट्स (माक 2.05) तक की हो सकती है। 1965 और 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में मिग-21 विमानों का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में भारतीय मिग ने चेंगडू एफ विमान (ये भी मिग का ही एक और वरियंट था जिसे चीन ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आए ‘‘प्रेसिडेंशियल रैफरेंस’’ पर यह नोटिस भेजा गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक प्रैसिडेंशियल रैफरेंस (राष्ट्रपति संदर्भ) पर जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती हैं।

नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश जी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंडुरकर की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 29 जुलाई को सूचीबद्ध की है। कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से मामले में सहायता करने का अनुरोध भी किया है।

8 अप्रैल, 2025 के ऐतिहासिक निर्णय में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

- **सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने नोटिस जारी करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख दी है, साथ ही एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को कोर्ट की सहायता करने का निर्देश दिया है।**

- **गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल 2025 को फैसला दिया था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए विधेयक को दबाकर रख नहीं सकते, हालांकि, आर्टिकल 200 में विधेयक पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई बिल विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर तीन माह में निर्णय लेना होगा और कोई देरी हो तो संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर ‘‘पॉकेट वीटो’’ या ‘‘पूर्ण वीटो’’ का हक नहीं है।**

- **इस आदेश पर 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने ‘‘प्रेसिडेंशियल रैफरेंस’’ भेजा, जिसमें 14 संवैधानिक सवाल उठाए, जिनमें प्रमुख था कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल को विधेयक की मंजूरी हेतु ‘‘समय सीमा’’ के लिए बाध्य कर सकता है। रैफरेंस कहता है कि संविधान में न्यायपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।**

और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में एक निर्दिष्ट समयसीमा की अनुपस्थिति के बावजूद विधेयकों पर सहमति देने में अनिश्चितकालीन देरी नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि इसमें कोई और देरी हो, तो उसका स्पष्ट कारण संबंधित राज्य को बताया जाना चाहिए।

इस निर्णय की अन्य मुख्य बातें थीं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो (राज्यपाल द्वारा बिना निर्णय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान मरम्मत के बाद वापस गया

तिरुवनंतपुरम (केरल), 22 जुलाई। ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान एफ-35 आखि़कार ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया है। लगभग एक महीने से भारत में खड़े रहे इस विमान ने आज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी है।

- **एफ-35 फाइटर जेट का हाइड्रॉलिक सिस्टम खराब हो गया था तथा उसे तिरुवनंतपुरम में आपात लैंडिंग करने पड़ी थी। ब्रिटिश इंजीनियरों को इसे ठीक करने में 38 दिन लगे।**

ब्रिटिश नेवी का यह एअरक्राफ्ट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है। इसने 14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। विमान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप प्रशासन अपने कार्यकाल के मध्य में है, पर अभी भी अमेरिकी नागरिक विभाजित हैं, ट्रंप के प्रशासन के बारे में

-अंजन राॅय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-
वॉशिंग्टन, 22 जुलाई। अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनावों से कुछ ही महीने पहले, अमेरिका में मतदाता ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर पहले की तरह ही विभाजित नजर आ रहे हैं, चाहे वह निष्ठा हो, या उनके कार्यकाल का मूल्यांकन। डॉनल्ड ट्रंप के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए दो मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। पहला है महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का मुद्दा, जहाँ ट्रंप के वफादार समर्थक भी बढ़ती कीमतों की मार महसूस कर रहे हैं। लोगों को, चाहे उनका राजनीतिक रङ्गान कुछ भी हो, लगता है कि कीमतें लगातार ऊँची बनी हुई हैं और इससे आम अमेरिकी का जीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप ने महंगाई के मुद्दे को बड़े प्रभावी ढंग से उठाया था। यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। बाइडन प्रशासन के शुरुआती दिनों में बहुत अधिक महंगाई देखी गई थी, जिसे बाद में काबू में लाया गया। लेकिन बदनामी तो हो चुकी थी। ट्रंप ने बार-बार इसे बाइडन को विफलता के रूप में दर्शाया और वादा किया कि वे कीमतों और जीवन-यापन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन बढ़े हुए दामों ने परिवारों के बजट को लगातार प्रभावित किया और अभी भी यह एक बड़ी चिंता बनी हुई है। तथापि, कुछ मतदाता मानते हैं कि नौकरी की संभावनाएँ और समग्र स्थिरता अब बेहतर हो रही है, भले ही जीवन की लागत अधिक हो। दूसरा मुद्दा है, एक सैक्स रैकेट स्कैंडल, जो मृत उच्च-प्रोफाइल

- **सब मानते हैं, महंगाई बढ़ी है, पर, ट्रंप के वफादार फिर भी यह मानते हैं कि बड़ी हुई महंगाई के बावजूद देश में शांति व ‘‘स्टेबिलिटी’’ (स्थिरता) है।**
- **दूसरा प्रमुख मुद्दा, ट्रंप प्रशासन के मूल्यांकन के बारे में है, उनकी (ट्रंप की) बाल यौनाचार के आरोपी ‘‘एपस्टीन’’ से नज़दीकी के बारे में। ट्रंप के पुराने वफादार व समर्थक अभी भी ट्रंप को निर्दोष मानते हैं, पर, कुछ कट्टर समर्थक भी अब यह मानने लगे हैं कि ट्रंप को खुलकर अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि, अब वह मोड़ आ गया है, जबकि जनता ‘‘सत्य व पूर्ण सत्य को जाने बगैर संतुष्ट नहीं होगी।’’**

सामाजिक हस्ती एपस्टीन से जुड़ा है। एपस्टीन के साथ नजदीकियों ने अमेरिका और इंग्लैंड के कई शीर्ष लोगों को संकट में डाल दिया, जिनमें किंग चार्ल्स के छोटे भाई भी शामिल हैं।

एपस्टीन पर सबसे गंभीर आरोप ये हैं कि उसने मशहूर हस्तियों के लिए ‘‘चाइल्ड सैक्स’’ का आयोजन किया। उदाहरण के लिए, प्रिंस एंड्रयू पर ऐसे ही आचरण का आरोप लगा था, जिसकी

ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का मूल्यांकन किया। एजेंसी ने अपने उस डेटा बेस का इस्तेमाल किया, जिसमें वो लोग शामिल थे, जिन्हें एजेंसी कई वर्षों से फॉलो कर रही थी। न्यूज़ चैनल ने उन लोगों को ट्वैक किया, जिन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उसके सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर उनसे संपर्क करके उनसे उनका मूल्यांकन लिया गया है। हालाँकि कई समर्पित ट्रंप समर्थकों ने अपना समर्थन कायम रखा है, लेकिन कुछ कट्टर समर्थकों ने भी अब यह मांग की है कि राष्ट्रपति और प्रशासन को ट्रंप की नैतिकता से जुड़ी बातों को लेकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए। कुछ वफादार तो यह विश्वास भी नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति सच्चाई बता रहे हैं, या उनके जवाब उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पा रहे हैं कि असली मुद्दा क्या था।

- **महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई ट्रेन धमाकों में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बाम्बे हाईकोर्ट ने इस आतंकी घटना के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस घटना में 189 लोग मरे थे व 820 गंभीर घायल हुए थे।**

बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

⊕

● ● ● ●

CMYK

विचार बिन्दु

नियम के बिना और अभिमान के साथ किया गया तप व्यर्थ ही होता है। –वेदव्यास

जांच और अभियोजन की खामियां दर्शाता अदालती फैसला

मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को विभिन्न स्थानों पर लोकल ट्रेनों में सात विस्फोट हुए, जिनमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए थे। इसके उन्नीस साल बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को उनके सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा और “यह विश्वास करना मुश्किल है कि उन्होंने अपराध किया है”। यह फैसला अपराध की जांच करने वाली एजेंसी और अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी लेकर आया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में अनेकों ऐसे फैसले आए हैं जिनमें बरसों से जेलों में बंद लोग बरी किए गये हैं। हालांकि ऐसे फैसले भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं विश्वसनीयता को स्थापित करते हैं किन्तु वे न्याय प्रक्रिया में देरी की ओर भी ध्यान खींचते हैं। साथ ही वे जांच एजेंसियों और अभियोजन पक्ष की खामियों व कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। वर्षों तक मुकदमा चलने के बाद अभियुक्तों की रिहाई भारतीय न्यायिक तंत्र की गंभीर और बहुआयामी समस्या के साथ सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पीड़ा को भी दर्शाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बरसों तक अदालतों में घसीटा जाता है और अंततः उच्च न्यायालय उसे बरी कर देता है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है कि क्या वह केवल एक न्यायिक निर्णय है या वर्षों की पीड़ा और अन्याय की स्वीकृति है। अधिकतर मामलों में ट्रायल कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाते हैं, परंतु ऊपर के न्यायालयों में अपील के दौरान यह स्पष्ट होता है कि साक्ष्य पर कमजोरियां थे या गवाहों की गवाही टिकने वाली नहीं थी। इससे ट्रायल अदालतों के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इस बार भी हुआ है जिसमें न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की विशेष पीठ ने मुंबई हादसों के बारे में कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में दर्ज करने में विफल रहा है और जिन सबूतों पर उसने भरोसा किया है, वे आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं। हाईकोर्ट ने 12 लोगों की दोषसिद्धि को रद्द करते हुए कहा कि गवाहों के बयान और आरोपियों से की गई कथित बरामदगी का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। इन 12 लोगों में से पांच को एक विशेष अदालत ने मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह मानना मुश्किल है कि आरोपियों ने अपराध किया है। इसलिए उनकी दोषसिद्धि रद्द की जाती है।” इस फैसले में अभियोजन पक्ष की कमजोरियों पर भी टिप्पणियां हैं कि वह मामले के महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा तथा बरामद वस्तुओं का खराब और अनुचित रखरखाव करके प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला। पीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष कथित अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में दर्ज करने में विफल रहा है।” उच्च न्यायालय ने मामले के कुछ आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा लगता है कि ये बयान उन्हें यातना देकर लिए गए थे। पीठ ने कहा, “इकबालिया बयान अधूरे और असत्य पाए गए हैं क्योंकि कुछ हिस्से एक-दूसरे को नकल हैं। आरोपियों ने यह साबित कर दिया है कि उस समय उन्हें यातनाएं दी गई थीं।” अदालत ने आरोपियों की पहचान परेड को भी खारिज कर दिया और कहा कि संबंधित पुलिस को ऐसा करने का कोई अधिकार ही नहीं था। उच्च न्यायालय ने गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों को भी स्वीकार करने से यह कह कर इनकार कर दिया कि “गवाहों के बयान विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं हैं और आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं हैं। गवाहों ने घटना के चार महीने बाद पुलिस के सामने शिनाख्त परेड के दौरान और फिर चार साल बाद अदालत में आरोपियों की पहचान की।” इन गवाहों को घटना वाले दिन आरोपियों को देखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला था ताकि वे बाद में उनकी सही पहचान कर सकें। न्यायधीशों ने कहा कि हमें ऐसा कोई कारण नहीं मिला जिससे उनकी स्मृति जागृत हो और चेहरे याद आ सकें।”

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में निर्दोष साबित होने पर सरकार द्वारा मुआवजा, पुनर्वास सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा रोजगार पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरसों तक मुकदमे झेलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिहाई भले ही कानूनी दृष्टि से न्याय का प्रतीक हो, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यह एक त्रासदी ही कही जाएगी।

अभियुक्तों पर कैसा सामाजिक व मानसिक दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने वर्षों जेल में बिताए, वे मानसिक रूप से टूट जाते हैं। उनकी पहचान समाज में ‘अपराधी’ के रूप में स्थापित हो जाती है, चाहे उन्हें बाद में निर्दोष घोषित कर दिया जाए। समाज में उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। रोजगार, शादी, और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसी चीजें उनसे छिन जाती हैं। एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया मंद न केवल व्यक्ति की आय प्रभावित होती है, बल्कि उसके परिवार पर भी भारी आर्थिक बोझ पड़ता है – कहींलों की फीस, कोर्ट की तारीखों पर जाना, नौकरी छूट जाना आदि। हालांकि कहा यह जाता है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेशन मगर भारत में जमानत के सिद्धांत को आमतौर पर पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। परिणामस्वरूप, आरोपी बिना दोष सिद्ध हुए सालों तक जेल में बंद रहता है। इसीलिए ऐसे में केवल दोषमुक्ति ही नहीं, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति को भी उतना ही अनिवार्य बनाए जाने की मांग होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यदि देश में सच्चे अर्थों में संवैधानिक और मानवीय न्याय की व्यवस्था करनी है, तो न्यायिक प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना होगा। सच तो यह है कि भारतीय न्याय व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी न्यायिक प्रणालियों में से एक है, परंतु यह समान रूप से धीमी और जटिल भी है। हमारे यहां ट्रायल कोर्ट की त्रुटियों पर भी यदा-कदा ऊपरी अदालतें नाराजगी जताते हुए टिप्पणियां करती हैं। बहुत बार निचली अदालतें साक्ष्यों की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाती या अभियुक्तों के पक्ष को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं देतीं, जिससे उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के बाद अभियुक्त बरी कर दिए जाते हैं।

हालांकि मुकदमे लंबे खिंचते हैं, परंतु उच्च न्यायालय कई बार न्याय की अंतिम आशा बनकर सामने आते हैं। वे तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा करते हैं और जांच तथा ट्रायल में हुई खामियों को उजागर करते हैं जैसा मुंबई की ट्रेनों में विस्फोटों के मुकदमे में हुआ है। उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई रिहाई कई बार न्यायिक दखल और विवेक की मिसाल बनती है, लेकिन यह भी सत्य है कि उस निर्णय तक पहुंचने में जितनी देर हुई, वह आरोपी के जीवन की अपूरणीय क्षति बन जाती है। यहां यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है – क्या वर्षों बाद अदालत से बरी हो जाना न्याय है? लंबे समय तक जेल में रहना, कोर्ट की तारीखों का बोझ, अपनों से बिछड़ना – यह सब किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकता है। कई मामलों में रिहा हुए लोगों को मानसिक रोगों से जूझते हुए भी पाया गया है। रिहाई के बाद जीवन को फिर से सामान्य पटरी पर लाना अत्यंत कठिन होता है। न तो समाज उसे सहज स्वीकार करता है, न ही उसका आत्मबल उसे फिर से जीवन में स्थापित होने देता है। इसलिए समाजशास्त्री व मनोवैज्ञानिक ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति की आवश्यकता प्रतिपादित करते हैं, ताकि बरी हुए लोगों का पुनर्वास हो सके और उन्हें समाज में पुनः स्थापित होने में सहयोग दिया जा सके। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में निर्दोष साबित होने पर सरकार द्वारा मुआवजा, पुनर्वास सहायता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग तथा रोजगार पुनर्स्थापन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। भारत में तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बरसों तक मुकदमे झेलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रिहाई भले ही कानूनी दृष्टि से न्याय का प्रतीक हो, परंतु मानवीय दृष्टिकोण से यह एक त्रासदी ही कही जाएगी। यह स्थिति न केवल हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती है, बल्कि बल्कि करुणा और उत्तरदायित्व की भावना से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। यदि हमें सच्चे अर्थों में अदालतों को न्याय के मंदिर बनाना है, तो हमें ऐसी व्यवस्था बनाने की तरफ बढ़ना होगा जिसमें किसी निर्दोष को वर्षों जेल में नहीं रहना पड़े क्योंकि किसी को लंबे समय तक बंदी बनाए रखने के बाद रिहा कर देना, न्याय नहीं – न्यायतंत्र की गम्भीर विफलता है। इस दर्द को समझा जाना चाहिए और न्याय प्रक्रिया को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए जिससे हर वह व्यक्ति न्याय पा सके जो वर्षों से केवल एक तारीख की उम्मीद में जी रहा है।

–अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

स्वच्छता में राजस्थान का परचम: नवाचार, निष्ठा और कुशल नेतृत्व की मिसाल बना



कुणाल वशिष्ठ

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत राजस्थान ने स्वच्छता और शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में देशभर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा 233 नगरीयनिकायों में 3 हजार 799 करोड़ की योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालय निर्माण, प्रयुक्त जल प्रबंधन, क्षमता संवर्धन और जन-जागरूकता जैसे विविध घटकों को शामिल किया गया है। राज्य में 219 करोड़ की लागत से अब तक 29961 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 8068 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राजस्थान के लाखों नागरिकों को स्वच्छ वातावरण के साथ-साथ सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं।

प्रयुक्त जल प्रबंधन के अंतर्गत एक लाख से कम जनसंख्या वाले 208 नगरीय निकायों में 1 हजार 785 करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है, जिनमें से 41 शहरों में कार्य आवंटित कर दिए गए हैं। ठोस

अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राज्य में 1372 करोड़ की लागत से 233 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 7 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 152 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य किया जा रहा है। इनमें से 153 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, 5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 76 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का कार्य प्रगतिरत है, जबकि 2 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र तथा 76 लाख घन मीटर से अधिक लेगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्य में 301 स्थाई मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित कर नागरिक संवाद और जनसहभागिता को और अधिक मजबूत किया गया है।

कचरे से समृद्धि की ओर बढ़ता राजस्थान :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के बहुमुखी विकास के लिए नवाचार को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खरों के निर्देशन में सीकर नगर परिषद ने “शून्य अपशिष्ट, शून्य लागत” मॉडल के तहत प्रतिदिन 125 टन कचरे का निस्तारण कर स्थानीय किसानों को 2 प्रति किलोग्राम दर से उच्च गुणवत्ता की खाद उपलब्ध करवाई है। जोबनर और बस्सी नगर निकायों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ऑन-साइट प्रशिक्षण देकर ठोस कचरा प्रबंधन में जोड़ा गया है, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। जयपुर के लांगडियावास स्थित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में प्रतिदिन 1000 टन कचरे का निस्तारण कर उससे 12 मेगा वाट



विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जो राज्य के सतत ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान की चमकदार उपलब्धि : स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ढूंगरपुर शहर को सुपर स्वच्छता लीग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर को प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में पहचान मिली। राज्य के 12 शहर देश के प्रथम 100 स्वच्छ शहरों में शामिल हुए हैं और पहली बार तीन शहरों को वाटर प्लस श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि राज्य के सभी 240 शहरों की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रत्याशित सुधार दर्ज हुआ है।

स्थायी परिवर्तन की ओर :

स्वच्छ ऊर्जा और हरित नवाचार की नई राह, राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब एक लाख परिवारों को निःशुल्क इंडक्शन कुकटॉप मिलेंगे, जिससे न सिर्फ धुएँ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि रसोई में ऊर्जा की नयी क्रांति भी आएगी। ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर बढ़ते हुए ग्राम पंचायतों में ‘बर्तन बैंक’ की अनुठी पहल शुरू की जा रही है, जिससे सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक के स्थान पर पुनः उपयोग योग्य बर्तनों का प्रयोग हो सके। उल्लेखनीय है कि अब तक जयपुर सहित कुल 41 जिलों की 1000 ग्राम पंचायतों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही, वेस्ट टू वेयर पार्क और स्लीन एंड टीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर जैसे

नवाचारों से राज्य में पर्यावरण संरक्षण को तकनीकी आयाम मिल रहा है, यह सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि हरित विकास की ओर निर्णायक यात्रा है। ये अभूतपूर्व निर्णय और उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में न केवल बुनियादी सुविधाएँ सुदृढ़ की हैं, बल्कि नवाचार, सहभागिता और समावेशी विकास के माध्यम से एक स्थायी और स्वच्छ भविष्य की नींव रखी है। राजस्थान की यह यात्रा न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

कुणाल वशिष्ठ, जनसंपर्क अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग।

राजस्थान में उच्च शिक्षा पर संकट : संविदा शिक्षकों की नई नीति और उसके गंभीर परिणाम



अशोक कुमार

राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई नीति, जिसके अंतर्गत राज्य के 335 राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों की नियुक्ति पांच वर्षों के अनुबंध पर की जाएगी, न केवल शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीति है, बल्कि यह उच्च शिक्षा की मूल

आत्मा और के मूल उद्देश्यों के भी प्रतिकूल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर में उच्च शिक्षकों के लिए जो वेतनमान निर्धारित किए हैं, वे सामान्य सेवाओं से कहीं अधिक हैं और इसके पीछे एक स्पष्ट सोच रही है – देश के श्रेष्ठतम मस्तिष्कों को शिक्षा और अनुसंधान की दिशा में प्रेरित करना। क्योंकि जब शिक्षक सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थल की दृष्टि से सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं, तभी वे शिक्षण, शोध और नवाचार में अपनी ऊर्जा और समर्पण दे सकते हैं।

राजस्थान की नई नीति में शिक्षकों को केवल 28,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा, जो कि द्वारा निर्धारित 57,700 रुपये न्यूनतम वेतन के लगभग आधे से भी कम है। यह स्थिति न केवल शिक्षकों की गरिमा के विरुद्ध है, बल्कि इससे युवाओं में उच्च शिक्षा

को करियर विकल्प के रूप में चुनने की इच्छा भी क्षीण होगी। एक तरफ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम शिक्षकों को अस्थायी संविदा पर अल्प वेतन में कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं, जो स्पष्ट रूप से दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।

शिक्षा केवल नौकरी नहीं होती, वह समाज निर्माण का कार्य है। एक सहायक आचार्य जब कॉलेज में प्रवेश करता है, तो वह विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, बल्कि उन्हें जीवन के उच्च मूल्यों, शोध की संस्कृति और नवाचार की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। यदि उसका स्वयं का भविष्य अनिश्चित हो, तो वह अपने छात्रों को स्थायित्व और लक्ष्य की प्रेरणा कैसे दे पाएगा?

विद्या संवल योजना के समाप्त करने और गुजरत मॉडल के आधार पर संविदा शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय

यह दर्शाता है कि सरकार तात्कालिक वित्तीय प्रबंधन को दीर्घकालिक शिक्षा नीति पर वरीयता दे रही है। क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिनमें शिक्षकों की योग्यता, सुरक्षा और प्रेरणा के साथ समझौता हो?

राजकीय महाविद्यालय पहले ही शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। शोध, नवाचार और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार तभी संभव है जब योग्य शिक्षक स्थायित्व और सम्मान के साथ कार्य कर सकें। तीन वर्षों के अंतराल पर प्राचार्यों का कार्यकाल बढ़ाने की योजना भी केवल पद की निरंतरता को सुनिश्चित करती है, न कि संस्था की गुणवत्ता को। आवश्यक है कि पदस्थापन और सेवा विस्तार की कोई भी योजना केवल अनुभव नहीं बल्कि निष्पक्ष मूल्यांकन के आधार पर हो।

यह नीति केवल एक शॉर्टकट

समाधान है, जो दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और स्थायी बनाना होगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय वेतनमान, सेवा सुरक्षा और शोध के लिए सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। तभी हम एक ऐसा शिक्षण तंत्र विकसित कर सकते हैं जो भारत को वैश्विक ज्ञान-शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर हो सके। शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए शिक्षक की पूर्णिका केंद्रीय है। यदि हम शिक्षा को भविष्य का निवेश मानते हैं, तो हमें शिक्षकों को केवल संविदा कर्मी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता के रूप में देखना होगा।

–अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

आलसर बास में पानी की टंकी की हालत खस्ता, ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर

राजलदेसर, (निसं)। राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती गांव आलसर बास में करीब 400 से अधिक घरों में लोग निवास करते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भी है, जहां पर विद्यार्थी अध्ययन करते

- टंकी ऊपर से पूरी तरह से टूट चुकी है, जिससे इस टंकी में कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु आदि देखने को मिल रहे हैं
- 33 वर्ष पूर्व टंकी का निर्माण करवाया था, लेकिन गांव के अंदर एकमात्र टंकी होने के कारण उसकी भी हालत इतनी खराब है कि पूरी जर्जर हो चुकी है

हैं। इनके लिये एकमात्र पीने के पानी की टंकी है।

ग्रामवासियों ने बताया रतनगढ़ के पूर्व विधायक स्व. जयदेव प्रसाद इंदौरिया ने 33 वर्ष पूर्व टंकी का निर्माण करवाया था, लेकिन गांव के अंदर एकमात्र टंकी होने के कारण उसकी भी हालत इतनी खराब है कि

पीना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूली बच्चों को भी इसी टंकी का पानी पिलाया जाता था।

गांव के लोगों ने बताया इससे पूर्व कांप्रेस व बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को इस समस्या को लेकर कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन किसी ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं



राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती गांव आलसर बास में करीब 33 वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है।

दिया। वर्तमान में बारिश का समय चल रहा है। यह टंकी विद्यालय के पास स्थित है। यहीं से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। गांव के प्रमुख लोगों ने बताया कि अगर समय रहते हुए सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान नहीं

देगी तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बिजली-पानी पर फोकस देती है, लेकिन पीने के पानी की यह हालत है जो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसके अलावा गांव के प्रमुख लोगों ने बताया कि चुनाव के समय राजनेता बड़े-बड़े वादे करके यहां से

चले जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद यहां तक नहीं आते। गांव की दूसरी प्रमुख मांग है जो है आलसर बास से आलसर तक करीब पांच किलोमीटर सड़क है। उसकी हालत इतनी खराब है कि पैदल आदमी नहीं चल सकता। वाहनों की हालत तो इतनी खराब हो जाती है कि कभी-कभी बड़ा हादसा होते हुए बाल-बाल बच चुके हैं, क्योंकि इस मार्ग पर अधिकांश कृषि की जमीन है, जिससे किसान इस मार्ग से गुजरते रहते हैं, लेकिन बार-बार राजनेताओं को सड़क को लेकर अवगत कराने के बावजूद किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राम मेघवाल, रामचन्द्र , हरिराम, अनूप सिंह, मोहनराम, जीवणराम, शंकर सुधार, निदेश, रामदयाल, रामचंद्र स्वामी, शंकर नाथ सहित दर्जनों ग्रामवासी मौजूद रहे।



पंडित अनिल शर्मा

वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज भद्रा दिन 3:34 तक रहेगी। बुध अस्त पश्चिम में रात्रि 2:55 पर होगा। आज मास शिवरात्रि है। आज से राष्ट्रीय सावन मास आरम्भ होगा। श्रेष्ठ चौघडिया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:13 तक, शुभ 10:52 से 12:33 तक, चर 3:54 से 5:35 तक, लाभ 5:35 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16

राशिफल

बुधवार 23 जुलाई, 2025

सावन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र रायः 5:54 तक, व्यापत योग दिन 12:34 तक, विष्टि करण दिन 3:34 तक, चन्द्रमा आज मिथुन राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-

वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज भद्रा दिन 3:34 तक रहेगी। बुध अस्त पश्चिम में रात्रि 2:55 पर होगा। आज मास शिवरात्रि है। आज से राष्ट्रीय सावन मास आरम्भ होगा। श्रेष्ठ चौघडिया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:13 तक, शुभ 10:52 से 12:33 तक, चर 3:54 से 5:35 तक, लाभ 5:35 से सूर्यास्त तक। राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:16

मेघ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों मदद-बंधुओं के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

तुला नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी।

वृश्चिक चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा शुभ नहीं है।

मिथुन मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। वाणी पर संयम रखें।

मकर परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।

कुंभ व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। कारोबारी अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

कन्या व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। अतिथियों के आयोजन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

लूणी नदी में पानी की आवक शुरू होने से किसानों के चेहरों पर खुशी

किसान लोगों ने ढोल बजाकर लूणी नदी में पानी की आवक का स्वागत किया

गुडामालानी, (निसं)। गुडामालानी क्षेत्र के किसानों के लिए वरदान साबित होने वाली मरू गंगा के नाम से विख्यात लूणी नदी में पानी की आवक शुरू होने पर किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। किसान लोगों ने ढोल बजाकर लूणी नदी में पानी के आवक का स्वागत किया।

बालोतरा, सिणधरी, गुडामालानी सिवाना सहित क्षेत्र के किसान लोगों के लिए मरू गंगा के नाम से लूणी नदी विख्यात है, क्योंकि लूणी नदी में पानी की आवक होने से किसानों को पानी के साथ हजारों रुपयों की बचत एवं साथ में फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। ऐसे में क्षेत्र के हजारों किसान मरू गंगा का मान-सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। लूणी नदी का पानी रतनपुरा नदी में पहुंचा और शाम तक गांधव तक पहुंच सकता है। नदी के पानी का तेज बहाव होने से नदी में दो तीन फीट पानी बह रहा है। किसानों ने बताया कि लगातार तीन बार लूणी नदी आई, जिससे जमीन में जलस्तर बढ़ना किसानों के लिए अच्छा है। जलस्तर बढ़ने से किसानों को अपनी फसलों



गुडामालानी क्षेत्र में “मरू गंगा” के नाम से विख्यात लूणी नदी में पानी की आवक शुरू हुई।

के लिए यह लूणी का पानी उपयोग में लेते हैं। लूणी नदी में पानी पहुंचने की खबर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलने

पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। रतनपुरा से लेकर गांधव तक ढाणियों में, खेतों में लोग मौजूद रहे। ऐसे में

तेज बहाव एवं पानी की आवक को देखते हुए उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा के द्वारा रतनपुरा पुल,

- गुडामालानी, सिवाना, बालोतरा, सिणधरी सहित क्षेत्र के किसान लोगों के लिए “मरू गंगा” के नाम से लूणी नदी विख्यात है

- लूणी नदी में पानी की आवक होने से किसानों को पानी के साथ हजारों रुपयों की बचत एवं फसल की पैदावार भी अच्छी होती है

अजा का फांटा पुल सहित बहावी क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्था देखने के साथ नदी के अंदर तथा खेतों में रहने वाले किसानों सहित आमजन को पानी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दी।

घर में घुसकर धारदार हथियार से युवक की हत्या

आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया, पुरानी रंजिश को लेकर वारदात की

श्रीगंगानगर, (निसं)। जिले के केसरीसिंहपुर में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान सुखविंदर सिंह उर्फ भौर (40) के रूप में हुई है। घटना रात की है।

पुलिस को दी शिकायत में मृतक के भाई परमजीत सिंह ने बताया कि सुखविंदर सिंह पुलिस थाना केसरीसिंहपुर के पास रहता था। उन्होंने करीब 11 साल पहले उपा नाम की महिला से शादी की थी। उपा 10 साल तक उनके साथ रही और एक साल पहले किसी और के साथ चली गई। 22 जुलाई

- मृतक के शरीर पर कई चोटों के निशान व आंगन में खून के निशान मिले

की सुबह करीब पांच बजे परमजीत सिंह को थाने से फोन आया कि उनके भाई की हत्या हो गई है। मौके पर पहुंचकर पता चला कि गांव के ही गोविंद सिंह पुत्र कुलवंत सिंह ने रात में घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान

मिले हैं। आंगन में खून के निशान भी मिले हैं। थाना प्रभारी बलवंत राम के नेतृत्व में पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि हत्या किसी रंजिश के चलते की गई है। गांव के ही आरोपी गोविंद सिंह ने वारदात के बाद खुद थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच एक महीने पहले किसी बात को लेकर झगड़ा होना सामने आया है। जिसमें मृतक ने आरोपी के साथ मारपीट की थी। इसी रंजिश में गोविंद ने यह वारदात की। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

लूट की वारदात करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। जिले के बैकरिया थाना पुलिस ने मारपीट कर पीड़ित से बाइक लूट की वारदात करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पीड़ित विरमराम निवासी देवरानमण सायरा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। उसने बताया कि मैं बाइक पर लौहारचया से मेरे घर देवरानमण जा रहा था। जहां बीच रास्ते रोड़ पर तीन व्यक्ति खड़े थे। जिन्होंने बाइक को रोककर मेरे साथ मारपीट कर बाइक छीनकर फरार हो गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक राजेन्द्रसिंह के सुपरविजन में बैकरिया थाना अधिकारी उत्तमसिंह मय टीम ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी राकेश उर्फ काकसी पुत्र दुदराम, नेताराम पुत्र रामराम तथा पिटादाम पुत्र थावरा राम निवासी मालवा का चौरा बैकरिया को गिरफ्तार इनके कब्जे से छिनी गई बाइक बरामद की।

ब्यावर, (निसं)। दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जघन्य अपराध के फरार आरोपी नाथूराम (45) पुत्र छोगाराम गुर्जर दस्तयाब करने हेतु बनाई चार टीमों द्वारा किये गये प्रयास से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फरारी के दौरान खेतों, मन्दिरों, पहाड़ियों व अलग-अलग गांवों में छुपता रहा था।

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला व वृताधिकारी वृत्त जैतारण के निकट सुपरविजन में थानाधिकारी पुलिस थाना रास धोलाराम उनि मय गठित पुलिस टीमों द्वारा दो साल की बालिका के साथ दुष्कर्म के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु अलग-अलग चार पुलिस टीमों का गठन किया जाकर

तलाश के दौरान परिवार व गाम्गीणों से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि आरोपी नाथूराम शांति प्रवृति का है और घर पर अकेला ही रहता है। घटना के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बन्द कर दिया, ताकि पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाये। सघन तलाशी अभियान चलाया गया, आम लोगों से हलिये के आधार पर पूछताछ की गई तथा मुखबियों से सूचनायें संकलित की गई। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने आरोपी को पुलिस थाना मसूदा के एक गांव से दस्तयाब किया जिससे पूछताछ जारी है।

जानकारी के अनुसार 16 जुलाई को पुलिस थाना रास पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि 13 जुलाई को नाथूराम ने दो साल की बच्ची को कुरकुरे दिलाने के बहाने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान व आरोपी की तलाश शुरू की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया।

स्वरूपसागर छलका, आयड़ नदी का बहाव तेज हुआ

मदार छोटा तालाब पर भी हल्की चादर चलना शुरू हुई

उदयपुर, (निसं)। स्वरूपसागर के चारों गेट चार-चार इंच खुले होने के बावजूद सीसारमा नदी से आवक बनी रहने से मंगलवार सुबह से स्वरूपसागर की पाल छलक गई और दरवाजों के दोनों छोर से चादर चलने लगी है। सीसारमा नदी में मंगलवार को जलस्तर 4 फीट रहा। मदार छोटा तालाब पर हल्की चादर शुरू हो चुकी है और मदार बड़ा तालाब का गेज 24 फीट के मुकाबले 21 फीट हो चुका है। स्वरूपसागर के गेट खुले होने और चादर भी चलने से आयड़ नदी में पानी का बहाव तेज होकर उदयसागर में

आवक बढ़ी है। उदयसागर का जलस्तर 24 फीट के मुकाबले 20 फीट हुआ है। इसके भी जल संसाधन विभाग कभी भी गेट खोल सकता है। आकोदडा बांध, मानसी चाकल बांध सहित कुछ जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। मदार के दोनों तालाब से पानी की आवक तेज होने पर फतहसागर का झरना चल सकेगा। फतहसागर का जलस्तर 13 फीट के मुकाबले 10 फीट 4 इंच है। फिलहाल स्वरूपसागर लिंक नहर से फतहसागर में पानी की आवक बंद होने से फतहसागर का जलस्तर स्थिर हो चुका है। अब मदार के दोनों

तालाब से या फिर बड़ी तालाब से पानी की आवक होने पर फतहसागर के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकेगी। मदार छोटा तालाब पर हल्की चादर शुरू हो चुकी है और मदार बड़ा तालाब तीन फीट खाली है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार इस सीजन में उदयपुर शहर में अब तक कुल उदयपुर शहर में 219 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अलसीगढ़ में 363, गोगुंदा 501, झाडोल 424, कोटडा 382, मदार 193, नाई 259, उदयसागर में 334 और वल्लभनगर में 398 मिलीमीटर बारिश हुई है।

पहाड़ियों पर एक साथ तीन लेपर्ड दिखाई दिए

डूंगरपुर, (निसं)। शहर के चमनपुरा मोहल्ले के पीछे की तरफ पहाड़ियों पर एक साथ तीन लेपर्ड दिखाई दिए। लेपर्ड दिखने के बाद से लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं लोगों ने लेपर्ड के रेस्क्यू की मांग की है।

जानकारी के अनुसार शहर के

- लोगों में दहशत का माहौल, लोगों ने लेपर्ड के रेस्क्यू की मांग की
- लेपर्ड के मूवमेंट को लोगों ने मोबाइल में कैद किया

चमनपुरा मोहल्ले के पीछे की तरफ पहाड़ियों में जंगल का इलाका है। लोगों का कहना है कि पहाड़ियों पर आए दिन लेपर्ड दिखते हैं, लेकिन सोमवार देर शाम के समय एक साथ तीन लेपर्ड दिखाई दिए। पहाड़ी की चोटी पर एक साथ तीनों लेपर्ड का मूवमेंट दिखा। लोगों ने अपने मोबाइल में भी इसे कैद किया। हालांकि ये लेपर्ड पहाड़ी से नीचे की तरफ नहीं आए। लोगों ने कहा कि लेपर्ड ने अब तक कभी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन हमेशा किसी घटना का डर रहता है। खासकर बच्चे कई बार पहाड़ी की तरफ चल जाते हैं। कॉलोनी के लोगों ने लेपर्ड का रेस्क्यू कर राहत पहुंचाने की मांग की है। पिछले दिनों भी शहर के बांसडवाड़ा कॉलोनी के पीछे की तरफ पहाड़ियों पर एक लेपर्ड दिखाई दिया था।

दवा खरीद के लिए जारी 9.50 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर सवाल खड़े हुये

पीबीएम अस्पताल में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 19 तरह की दवाएं खरीदने के लिए टेंडर जारी हुये हैं

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम अस्पताल में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 19 तरह की दवाएं खरीदने के लिए जारी 9.50 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इन दवाओं में दस तरह की दवाएं केवल कैंसर से संबंधित हैं, जबकि क्रय समिति में कैंसर का डॉक्टर ही शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना, आरजीएसएच के तहत विभिन्न विभागों में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए 9.50 करोड़ की दवाएं खरीदने के लिए टेंडर किए गए हैं। ई-प्रोक्युमेंट के माध्यम से टेंडर 18 जुलाई को अपलोड किए गए थे। मेडिकल कॉलेज की साइट पर नजर आए तो पीबीएम के डॉक्टरों में खलबली मच गई। कुल 19 तरह की

- दवाओं में दस तरह की दवाएं केवल कैंसर से संबंधित हैं, जबकि क्रय समिति में कैंसर का डॉक्टर ही शामिल नहीं है

दवाओं के टेंडर एक साल के लिए किए गए हैं। इनमें दस महंगी दवाएं केवल कैंसर की हैं। इनमें से पांच ऐसी हैं, जिनका कभी कैंसर अस्पताल में उपयोग हुआ ही नहीं। यानी सरकारी आपूर्ति में भी यह दवाएं कभी नहीं मंगवाई गईं। कैंसर विशेषज्ञों ने भी कभी उनकी मांग नहीं की। विशेषज्ञों का कहना है कि जयपुर के स्टेट कैंसर सेंटर पर भी इन दवाओं का उपयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा पांच ऐसी दवाओं को भी टेंडर में शामिल किया गया है, जिनकी सरकारी आपूर्ति है। सबसे चौकाने वाली बात

यह है कि इन दवाओं की खरीद के लिए कैंसर विभाग की ओर से कोई मांग जारी नहीं हुई। सेंट्रल ड्रग वेयर हाउस से एनएसटी तक नहीं मांगी गई। बिड दस्तावेज पर अधीक्षक डॉ. सुरेंद्र कुमार ने बताया कि डॉ. सुभाष गोड़, डॉ. मनोज माली और वरिष्ठ लेखाधिकारी अभिषेक गोयल के हस्ताक्षर हैं। कैंसर के किसी विशेषज्ञ को इसमें शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसे में अचानक यह टेंडर जारी करने के कारणों को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आशंका है कि किसी फर्म विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य

से यह टेंडर किए गए हैं। पीबीएम में करीब 1400 तरह की दवाओं की खरीद के लिए पिछले साल 50 करोड़ के रेट कान्ट्रैक्ट कुछ कंपनियों से किए गए थे। यह अभी खत्म नहीं हुए हैं। इस टेंडर के चलते कुछ कंपनियों को 50 लाख रुपए से अधिक की दवाएं उपयोग में नहीं आने के कारण लौटाई जा चुकी हैं। नियमानुसार अवधि पार होने से छह महीने के भीतर यदि दवाओं का उपयोग नहीं किया जाता तो वापस फर्म को लौटानी पड़ती है। ऐसे में 9.50 करोड़ के टेंडर करना किताना जायज है, समझा जा सकता है। हैरत की बात यह है कि यह टेंडर भी ऐसे समय किए हैं जब राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी पर 100 करोड़ की देनदारियां हैं। बाजार से दवाओं की खरीद नहीं हो पा रही। सरकारी आपूर्ति

भी कम है। आए दिन आरएमएससीएल को पत्र लिखे जा रहे हैं। डॉ. सुरेंद्र बेनीवाल, एचओडी, मेडिकल ऑनकोलॉजी ने बताया कि पीबीएम स्तर पर कैंसर की दवाएं खरीदने के टेंडर होते हैं, लेकिन कतीन साल से हमारे विभाग से किसी भी डॉक्टर को समिति में शामिल नहीं किया जाता। यह सही है कि नए टेंडर में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो उपयोग में नहीं आतीं। हमसे कोई मांग भी नहीं मांगी गई है। डॉ. सुरेंद्र कुमार, अधीक्षक, पीबीएम अस्पताल बीकानेर का कहना है कि पिछले साल वाली रेट कान्ट्रैक्ट पूरी होने का समय आ गया है। दवाओं की जरूरत कभी भी पूर नहीं आ रही है, इसलिए आरसी की गई है। कैंसर विशेषज्ञ को शामिल क्यों नहीं किया, इसका पता लगाया जाएगा।

डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 18 अगस्त से

बीकानेर, (निसं)। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने डीएलएड प्रथम वर्ष –2025 की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया

है। राज्य के 376 डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 24500 अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 18 अगस्त से शुरू होंगी। यह परीक्षाएं 29 अगस्त तक आयोजित की

जाएंगी। पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि अभ्यर्थी के अध्ययनरत जिले में ही परीक्षा का केंद्र आवंटित किया जाएगा।

कार के कांच तोड़ लैपटॉप चुराये

उदयपुर, (निसं)। शहर के भूपालपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ कार के कांच तोड़कर दो लैपटॉप चुरा ले जाने का प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित कविश श्रीमाली पुत्र राकेश श्रीमाली ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि मैं व मेरा भाई हार्दिक दोनों 18 जुलाई रात में एवन स्कूल के सामने होटल वेस्टलेण्ड के पास कार खड़ी कर पिज्जा खाने गए। कुछ ही समय बाद लौटे तो पीछे का कांच टूटा हुआ एवं कार में रखे दो लैपटॉप मय बैग गायब थे। इसको देख इधर-उधर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

जेवरात चोरी

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर के बाघपुरा थाना पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ जेवर व सामान चुरा ले जाने का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरालाल पुत्र देवीलाल मासिंगपुरा बाघपुरा ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि अज्ञात चोर 21 जुलाई रात में मकान से सोने-चांदी के जेवर व ची तेल चुरा ले गए। इसका पता चलने पर पुलिस को जेवरात की सूची बाद में देने की सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया।

कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय)रणथम्भौर टाईगर रिजर्व करौली

Mail ID-dcfb.kroli.forest@rajasthan.gov.in Phone No. 07464-297007

क्रमांक-एफ़/निविदा/उवसं (द्वितीय)/2025-26/दिनांक-

Notice Inviting Bid

Bids for Construction of Naka/Chokri Khoda Ka Nala Range Wildlife Mandrayal are invited from interested bidders upto 5.00 PM Date 25.07.2025. Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (https://eproc.rajasthan.gov.in. http://sppp.rajasthan.gov.in) of the state website. The approximate value of the procurements is 18.47/-Lacs.

NIB CODE. FOR2526A0737, UBN CODE. FOR2526WSOB00832

(Hari Singh Dah)

Deputy Conservator of forest & Dy Field Director II

DIPRC/10088/2025Ranthambhore Tiger Reserve Karauli

नगर निगम जोधपुर-उत्तर

क्रमांक:- न.जि.जी.-उत्तर / 2558दिनांक:- 21.07.2025

:: ई-निविदा सूचना ::

(UB NO. DLB2526WSOB11967)

नगर निगम जोधपुर-उत्तर की ओर से Repairing and New Development work in Nagar Nigam Building Near Polytechnic college का कार्य हेतु ऑनलाईन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्तें आदि http://eproc.rajasthan.gov.in. www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.urban.rajasthan.gov.in/mcinj पर देखी जा सकती है।

आयुक्त

राज.सं.वाढ / सी / 25 / 6605नगर निगम जोधपुर-उत्तर

कार्यालय अधीक्षक एवं पदेन परियोजना प्रबन्धकवाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, सलुम्बर

क्रमांक- एफ़/निविदा/PMKSY 2.0 /2025-26/374दिनांक- 15.07.2025

ई निविदा सूचना 12-13/2025-26

पीएमकेएसवाये 2.0 (एनआरएम) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत झल्लारा, सलुम्बर (कुल 2 पैकेज) में जलप्रहरण विकास कार्यों के लिए बीड, अनुमानित मूल्य 219.32 लाख रुपये दिनांक 25.07.2025 को सायं 5.00 बजे तक इच्छुक बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती है। बोलियों से सम्बन्धित विस्तृत विवरण राज्य सरकार के पोर्टल (https://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.rajasthan.gov.in/) पर देखे जा सकते हैं।

यूएनबी संख्या- WSC2526WSOB00797, WSC2526WSOB00798

अतिरिक्त अभियंता एवं पदेनपरियोजना प्रबन्धक

वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, सलुम्बर

DIPRC/10099/2025

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं पदेन सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा (राज.)

क्रमांक-स्टोर/ई-निविदा/2025/4065दिनांक- 13.07.2025

ई-बोली आमंत्रण सूचना 03/2025

राजस्थान के राज्यपाल मोहनलाल जी ओर से राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के लिये निम्नलिखित सामग्री/सेवाओं के उपभोग हेतु ईच्छुक निविदादाताओं, पंजीकृत आवेदनिकाओं एवं सेवाप्रदाता एजेंसियों से ई निविदाओं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.उपानम की विषय वस्तुराशि (लाखों में)UBN NO.

1मेन पावर : (हैब्स, इलेक्ट्रिशियन, पलम्बर, ड्राईवर लिफ्टमैन, फायरमैन, योकी, ड्रक, सलायक रेडियोघाण्ट, टेलीमैन, नैत्र सहायक इत्यादि)98.00MHS2526SLRC02691

2कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन व बिना मशीन फार्मासिस्ट95.00MHS2526SLRC02690

विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निम्नलिखित लिंकि व समय तक http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं पदेन सचिव आर.एम.आर.एच. जिला चिकित्सालय दौसा (राज.)

DIPRC/10028/2025

कार्यालय नगरपालिका पोकरण जिला जैसलमेर राजस्थान (345021)

क्रमांक / नपापो / 25 / 2588दिनांक :- 16.07.2025

:: ई-निविदा सूचना ::-

नगरपालिका पोकरण की ओर से नगरपालिका पोकरण सक्षम श्रेणी एवं अन्य विभागों के संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युमेंट प्रक्रिया से सिविल कार्य हेतु ऑनलाईन दि-फक्की बोली अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।। कार्य के लिए धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नगरपालिका पोकरण में सक्षम संवेदकों द्वारा 2 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक अधिशाही अधिकारी नगरपालिका पोकरण एवं टेण्डर प्रोलेसिंग शुल्क नियमानुसार / - रू म.ड. R.S. JAIL RAJ. के नाम से देना होगा। निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://eproc.rajasthan.in व http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB NO- DLB2526A3658

UBN NO- DLB2526WSOB11653

अध्यक्ष

अधिशाही अधिकारी

राज.सं.वाढ / सी / 25 / 6597नगरपालिका पोकरणनगरपालिका पोकरण

Office of The BDO cum Program Officer (EGS) Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

No. 882Date- 16.07.2025

Notice of Inviting Bid

Bid for Rate Contract of Construction Material Supply under MGNAREGA, Work tenders/Cleaning Work of various work as below are invited from interested bidders under various Gram Panchayats of Panchayat Samiti sayla. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://proc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raji.ni.in) of the state; and notice board of this office.

Name of Gram PanchayatUBINEstimate Bid cost

हल्ली नीलाम्पी ठेका पं. सं. सायलाZJR2526GSRSC0064603.50 Laks

Khellawas (Work Tender)ZJR2526GSRSC0064710.00 Laks

ZJR2526GSRSC0064810.00 Laks

ZJR2526GSRSC0064918.00 Laks

Khetlawas (Narega RC)ZJR2526GSRSC0065060.00 Laks

Tikhi (Narega RC)ZJR2526GSRSC0065150.00 Laks

Tikhi (Cleaning WorkRC)ZJR2526GSRSC006525.28 Laks

Elana (Re-Narega RC)ZJR2526GSRSC0065380.00 Laks

Jeewana (Narega RC)ZJR2526GSRSC0065450.00 Laks

Taliyana (Narega RC)ZJR2526GSRSC0065650.00 Laks

BDO Cum Program Officer (EGS) Panchayat Samiti Sayla (Jalore)

DIPRC/10156/2025

कार्यालय नगरपरिषद, राजसमन्द

जिला परिषद रोह, राजनगर

टेलिकोन नं. 02952-220034, फ़ैक्स नं. 02952-221233, ई-मेल rajsamandnagarpalika@gmail.com

क्रमांक : एक/नगर/इजी/ई निविदा /12 / 2025-26 / 3408 दिनांक :- 21.07.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 12/2025-26

नगर परिषद राजसमन्द द्वारा विकास कार्यों हेतु समस्त विभागों में पंजीकृत संवेदकों, कम्पनी, संगठनों / संस्थानों से ई-प्रोक्युमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन तकनीकी व वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

निविदा कार्यक्रम

कार्य की संख्या

कार्यों की अनुमानित लागत

निविदा अपलोड की तिथि

निविदा डाउनलोड प्रारम्भ तिथि

ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की तिथि

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि

ऑनलाईन निविदा हेतु वेबसाइट

दोष निवारण अक्की

UBN NO-

राज.सं.वाढ / सी / 25 / 6590समाप्तिआयुक्त

तिथि व समय

151.95 लाख

22.07.2025 08:00PM

23.07.2025 09:00AM

04.08.2025 06:00PM

05.08.2025 01:00PM

05.08.2025 04:00PM

http://eproc.rajasthan.gov.in

DLB2526WSOB11912, 11915, 11917 & 11919

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका)

जिला परिषद राजसमन्द ईकाई एवं रिजर्व सेल, पोपाल नगर, बरौदिया बस्ती, रवेड जंक्शन के पास, जयपुर, पिन नं.-0141-2209370

क्रमांक :- बीबीएम/राज/रवेड/2025/240

ई-निविदा प्रपत्र

बीबीएम राजीविका एवं रिजर्व सेल, जयपुर के अन्तर्गत भोजन एवं कंटेनरिंग सेवाओं हेतु दर अनुबंध बाबत पात्र निविदादाताओं से ऑनलाईन तकनीकी और वित्तीय निविदाएं आमंत्रित करने हेतु आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

Sr. No.Scope of Work/ServicesEstimated ValueBid SecurityBid form Feee-Processing FeeLast Date & Time for bid submission dateDate & Time for Opening of Technical BidsDate & Time for Physical DD Deposit in DPMM OfficeValidity of bids

1.Food & Catering Services60.00 Lacs120000/-1000/-1000/-06.08.25 12.00 noon06.08.25 02.00 pm06.08.2025 1.00 PM90days from the date of submission of bids

ई-निविदा की निविदा प्रपत्र शुल्क 1000/- रूपये तथा बिड प्रभुति राशि 120000/-रूपये की डी.डी./बैंकर्स चेक Rajasthan Ajivika Vikas parishad के पक्ष में तथा ई-प्रोसेसिंग शुल्क 1000/- रूपये का डी.डी./बैंक की Scanned Copies भी भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड स्वीकार नहीं होगी। ऑनलाईन ई-निविदा e-proc portal अपलोड किया जाएगा। निविदादाताओं द्वारा अपने ई-निविदा प्रपत्र के साथ सम्पन्न दस्तावेजों को सील के पृथक् आत्म सत्यापन कर अपलोड किया जाएगा, साथ ही निविदा प्रपत्र में विस्तृत विवरण www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in पर जाकर भी डाउनलोड की जा सकती है। UBN No. - RGA2526SLRC00114

सह.सह.र/सी/25/6630जिला परिषद राजसमन्द, राजीविका, जयपुर

‘अधिकारी पेंडिंग फाइलों का जल्द निस्तारण कर आमजन को दे राहत’

आयुक्त ने निगम अधिकारियों को सड़कस्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य के लिए ठोस प्लान बनाने के निर्देश दिए



जयपुर। नगर निगम हेरिटेज आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान आयुक्त निधि पटेल ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आमजन की समस्याओं का जल्द निस्तारण करें। इस दौरान निगम आयुक्त ने ऑनलाइन पोर्टल राजकाज पर पेंडिंग शिकायतों को लेकर प्रत्येक निगम अधिकारी से वन टू वन संवाद किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि ऑनलाइन पेंडेंसी को बग़ाय़ा नहीं जाएँ, अपितु नियत समय में ही समस्याओं का ठोस निस्तारण कर राहत प्रदान की जाएँ।

जोन उपायुक्त अपनी टीम के साथ करें समीक्षा बैठक:-

इस दौरान निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने कहा कि संपर्क पोर्टल या अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकांश समस्याएँ सीवर, सफाई व्यवस्था को लेकर ही आ रही हैं। ऐसे में हेरिटेज निगम के

उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जिन जगहों पर सीवर या सफाई संबंधी समस्या ज्यादा आती हो, वहां पर निगम अधिकारी खुद मौके पर जाएँ और आमजन से संवाद कर समस्या का निदान कराएं

कि वे अपने अपने जोन में सड़क, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के निस्तारण के लिए ठोस प्लान बनाएं और इन कार्यों की ऑडिट भी कराएं। जिससे निर्माण कार्य समय पर कम बजट में गुणवत्ता पूर्ण किया जाएँ कार्य:-

वहीं परकोटे में हो रहे नए निर्माण कार्यों को लेकर हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए

कार्यशाला प्रतिभागियों की संयुक्त ध्रुवपद प्रस्तुति आज

जयपुर। जवाहर कला केन्द्र की ओर से आयोजित ध्रुवपद गायन प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह बुधवार 23 को आयोजित किया जाएगा। सायं 5 बजे सभी प्रतिभागी संयुक्त ध्रुवपद गायन की प्रस्तुति देंगे। 7 से जारी कार्यशाला में घरानेदारी के साथ कार्यशाला की विशेषज्ञ गुरु विदुषी प्रोफेसर डॉ मधु भट्ट तैलंग एवं उनके गुरु पद्म पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग द्वारा सृजित रचनाओं के नवाचार ख़ास होंगे।

गोविंद देव जी मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजन के पोस्टर का विमोचन

जयपुर। हरियाली अमावस्या 24 जुलाई कनक घाटी स्थित गोविंद देव जी ठिकाने के काला महादेव मंदिर में पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया जाएगा।

- कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रशांत शर्मा के आचार्यत्व में 21 वैदिक विद्वानों की टोली द्वारा किया जाएगा

मंगलवार को गोविंद देव जी मंदिर में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर महंत रामरज दास त्यागी, डॉ. प्रशांत शर्मा, घाट के बालाजी सुरेशनाथार्य, आचार्य आशुतोष महाराज, धर्मरक्षा समिति अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, गढ़ गणेश मंदिर से गौरव मेहता, धर्म प्रचारक विजय शंकर पांडेय सहित अनेक विशिष्ट ज्ञन उपस्थित थे। आयोजन में 200 से अधिक जोड़ों ने पंजीकरण



महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में मंदिर के सेवाधिकारी मानस गोस्वामी ने आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया।

कराया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. प्रशांत शर्मा के आचार्यत्व में 21 वैदिक विद्वानों की टोली द्वारा किया जाएगा। आयोजन की व्यवस्थाओं में 20 स्वयंसेवकों की टीम तैनात रहेगी। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। विभिन्न तीर्थों के जल और दुग्ध मिश्रित जल से महाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान रूढ़ी पाठ होंगे। फूलों से मनोरम श्रृंगार कर सामूहिक आरती की जाएगी।

काला महादेव को रामेश्वरम रूप में सजाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि श्रावण मास की हरियाली अमावस्या पर पार्थिव शिवलिंग पूजन करने से पितृ दोष, कालसर्प दोष, व्यापार में वृद्धि, सुख-समृद्धि तथा मनोकामना पूर्ति जैसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। आयोजन में पुरुषों को सफेद धोती-कुर्ता या कुर्ता-पाजामा तथा महिलाओं को लाल या पीली साड़ी पहन कर आनी होगी।

हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी ने ग्रेटर निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

- कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की उद्यान शाखा में हाल ही में हुए "वन टाइम प्लान्टेशन" से संबंधित टेंडरों में अनियमितताओं की शिकायत मंगलवार को ग्रेटर निगम कमिश्नर डॉ. गौरव सैनी के पास पहुंची। हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि, ग्रेटर निगम में 30 लाख रुपए से कम के टेंडरों में राजस्थान पारदर्शिता और सार्वजनिक खरीद अधिनियम (आरटीपीपी एक्ट) के नियमों के विपरीत मनमानी शर्तें जोड़ी गईं, जिनका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाना प्रतीत होता है।

यूनियन अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने बताया कि, अर्थव्यवस्था में भी टेंडर जारी किए हैं, परंतु वहां 30 लाख रुपए तक कोई शर्त नहीं लगाई गई। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने भी पूरी पारदर्शिता रखी। इससे ग्रेटर निगम की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

रघुवीर शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी 16 जुलाई को इस संदर्भ में ज्ञापन



यूनियन अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने आयुक्त गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा ।

से बाहर होते दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हैरिटेज नगर निगम ने भी टेंडर जारी किए हैं, परंतु वहां 30 लाख रुपए तक कोई शर्त नहीं लगाई गई। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने भी पूरी पारदर्शिता रखी। इससे ग्रेटर निगम की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

रघुवीर शर्मा ने कहा कि पूर्व में भी 16 जुलाई को इस संदर्भ में ज्ञापन

दिया गया था, परंतु आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरिटेज सिटी कॉन्ट्रेक्टर्स सोसायटी की ओर से कहा गया कि, ग्रेटर निगम के सभी जोन में एक तरफ तो 5 से 11 प्रतिशत तक कम दर पर कार्यदिश दिए जा रहे हैं, परंतु अगर किसी टेंडर में 10 से 11 प्रतिशत कम दर प्राप्त हो रही है तो अधीक्षण अभियंता और वित्तीय सलाहकार द्वारा "री - टेंडर" अथवा "नेगोसिएशन"

- यूनियन अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने आयुक्त को शिकायत में बताया कि, उद्यान शाखा ने आरटीपीपी एक्ट के विपरीत मनमानी शर्तें जोड़ी, इससे फर्म विशेष को फायदा पहुंचाने की संभावना
- 30 लाख से कम के टेंडर में जेडीए और हैरिटेज निगम में शर्तें नहीं, फिर ग्रेटर निगम में क्यों?

की टिप्पणी करके फाइलें लौटाई जा रहा है। ऐसे में यहां अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं।

तमाम शिकायतें सुनने के बाद आयुक्त गौरव सैनी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवाने का आश्वासन दिया है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा कर जयपुर लौटे श्रद्धालु

जयपुर। पांच वर्षों के अंतराल के बाद गत 4 जुलाई को लिपुलेख मार्ग से प्रारंभ हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए राजस्थान के श्रद्धालु 22 दिन बाद मंगलवार को सुकशाल वापस जयपुर लौट आए। तीर्थयात्रियों का दल सोमवार रात दिल्ली पहुंचा, जहां गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर सेंटर पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सभी श्रद्धालु अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। राजस्थान से यात्रा में सम्मिलित हुए वरिष्ठ राजेश नागपाल, नरेंद्र बैद और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एस संगंधि भी इस दल का हिस्सा थे। मंगलवार शाम को चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान जी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान

महिला की चेन तोड़ भागे बाइक सवार बदमाश

जयपुर। मानसरोवर थाना इलाके में दिनदहाड़े एक बाइक सवार बदमाश ने स्कूटी से जाती महिला के गले से सोने की चेन और पैंडल तोड़ लिया। घटना थाने से महज कुछ दूरी पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मानसरोवर थाना पुलिस के अनुसार कि चेन स्नेचिंग की वारदात प्रेरणा जैन (35) निवासी मानसरोवर के साथ हुई है। जो सोमवार दोपहर अपनी छह वर्षीय बेटी को सेक्टर 5 स्थित प्राइवेट स्कूल से स्कूटी पर लेकर घर लौट रही थी। इस दौरान मानसरोवर के महिला थाना (साउथ) से पचास मीटर दूर पर पीछे से आए बाइक सवार एक बदमाश ने बाइक को स्कूटी के पास धीमा करते हुए उसके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। इससे पहले महिला कुछ समझ बदमाश कुछ सेकेंड में ही आंखों से ओझल हो गया।

पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश की जा रही है।

मंदिर की दहलीज को प्रणाम कर दान पात्र चोरी कर ले गया बदमाश

जयपुर। हरमाडा थाना इलाके में एक मंदिर से दानपात्र चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में बदमाश मंदिर का गेट खोलकर अंदर घुसा। और फिर मंदिर की दहलीज को प्रणाम कर दान पात्र उठा चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

जांच अधिकारी एसआई प्रमोद कुमार ने बताया कि थाना इलाके के गोविन्दपुरा निवासी गोविंद शरण जांगिड़ ने मामला दर्ज करवाया है कि गोविन्दपुरा में खाखीजी महाराज का मंदिर है। जहां चोरों ने चोरी की नीयत से मंदिर को निशाना बनाते हुए मंदिर का गेट खोलकर बदमाश अंदर घुसे। मंदिर में रखे दानपात्र को चोरी कर ले गए। मंदिर पूजा करने आने पर दान पात्र गायब मिला। वहीं मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर चोर की कतूत कैद मिली। जहां मंदिर में एक बदमाश अंदर आया। गेट खोलकर अंदर घुसे बदमाश मंदिर में रखा दानपात्र उठाकर चोरी कर ले गया। मंदिर में चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चोरी गए दानपात्र में हजारों रुपए थे। पुलिस फुटेज में कैद हुए चोर की तलाश कर रही है।

शादी का झांसा देकर तीन साल तक एक युवती से देह शोषण

जयपुर। रामगंज थाना इलाके में शादी का झांसा देकर युवक ने तीन साल तक एक युवती से देह शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने आरोपित युवक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि राजा पार्क की रहने वाली युवती ने मामला दर्ज करवाया है कि कुछ साल पहले उसकी मुलाकात आरोपित से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपित ने उससे दोस्ती कर ली। मिलने-जुलने के दौरान आरोपित ने उसके सामने शादी करने का झांसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि जुलाई-2022 में मिलने के बहाने उसे अपने यहां बुलाया। मिलने जाने पर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर शादी करने का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर उसका देह शोषण करने लगा। पिछले करीब तीन साल तक आरोपी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर देह शोषण किया। जून-2025 में शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपित ने मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता थाने पहुंची।

काले हनुमान-गोविंद देवजी के किए दर्शन

तीनों यात्रियों ने अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया। जयपुर में परिजनों, श्रद्धालुओं एवं शुभचिंतकों ने सभी का माल्यार्पण कर आत्मीय स्वागत किया। यात्रियों ने बताया कि 21000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर की यह यात्रा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण रही। यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा डेरापुक से आरंभ हुआ, जहां 15000 फीट से चढ़कर 19500 फीट तक जाना पड़ा। संकरे और सीधी चढ़ाई वाले मार्ग में ऑक्सीजन की कमी का अनुभव हुआ। कई यात्रियों को

ऑक्सीजन सपोर्ट भी देना पड़ा। मेडिकल टीम ने सभी यात्रियों की निरंतर देखभाल की। ऊंचे-ऊंचे हिमालयी पर्वतों के मध्य बहती नदियों के साथ तीर्थयात्रियों ने ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठिन मार्ग पार किया। यात्रियों ने साझा किया कि यात्रा के दौरान अधिकांश समय मौसम बिल्कुल अनुकूल रहा। केवल एक दिन बारिश और तेज हवाएं चलीं। शेष पूरी यात्रा में मौसम साफ रहा। इसे उन्होंने भोलेनाथ की विशेष कृपा बताया। अंतिम पड़ाव में टकलाकोट पहुंचकर दल ने चीन सीमा से भारत में प्रवेश किया और उत्तराखंड के रास्ते दिल्ली पहुंचा। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन के साथ आनंदपूर्वक यात्रा की।

पौएम सूर्य घर योजना में राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6 लाख 13 हजार लाभान्वित परिवारों से 1781 मेगावट क्षमता के हुए समझौते : मदन राठौड़

एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने यह जानकारी सदन में दी। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि देश सरकार की ओर से ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाई जाती है। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजस्थान, गुजरात और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पौएम

‘मोदी सरकार के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान में तेजी से हो रहा विकास’

सूर्य घर योजना के लिए 1032 करोड़ तथा पौएम कुसुम योजना के तहत 293 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें राजस्थान को दोनों योजना के तहत 257 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार के प्रयास से 30 जून तक राजस्थान में 37818 मेगावाट क्षमता, गुजरात में 37494 मेगावाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5048 मेगावाट के तवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह इन क्षेत्रों में 80361 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से ऊर्जा क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण तक दिया जा रहा है। सूर्य मित्र योजना के तहत इन क्षेत्रों के 63713 व्यक्तियों को, वरुण मित्र योजना में 1276 और ऊर्जा मित्र कार्यक्रम में 601 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष बने गिरीश जैन

जयपुर। रमन पारीक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपने स्वास्थ्य कारणों से महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के पश्चात कैडर के संरक्षक विपिन गोयल द्वारा कैडर के सदस्यों/ कार्यकर्ता की सदस्यों से प्राप्त राय उपरांत महासंघ के संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिरीश जैन ने राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। वर्तमान में जैन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस अवसर पर महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गिरीश जैन ने बताया महासंघ द्वारा 21 सितंबर को होने वाले आगामी आयोजन "संगम-2025" को विशाल स्वरूप में आयोजित करने एवं कैडर की लंबित मांग को पूर्ण करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

‘मोदी सरकार के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान में तेजी से हो रहा विकास’

सूर्य घर योजना के लिए 1032 करोड़ तथा पौएम कुसुम योजना के तहत 293 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें राजस्थान को दोनों योजना के तहत 257 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार के प्रयास से 30 जून तक राजस्थान में 37818 मेगावाट क्षमता, गुजरात में 37494 मेगावाट और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5048 मेगावाट के तवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह इन क्षेत्रों में 80361 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

विवाहिता ने फांसी का फंदालगाकर की आत्महत्या

जयपुर। वैशाली नगर थाना में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विवाहिता तीन साल पहले उसने लव-मैरिज की थी। मृतका के परिवार की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।

सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर आलोक गौतम ने बताया कि बहरोड़ के कोटपूतली की रहने वाली भारती कंवर (25) ने फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या की है। तीन साल पहले भारती ने गांव के ही रहने वाले आकाश सिंह के साथ भागकर लव-मैरिज की थी। शादी के बाद से वैशाली नगर स्थित कोस्मो कॉलोनी में वह अपने पति आकाश के साथ रह रही थी। आकाश और भारती दोनों एक ग्राइवेट बैंक में नौकरी करने लगे। गत दिनों पहले पति के सोने के बाद कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आकाश ने जागने पर भारती को ढूंढा तो दूसरा कमरा अंदर से बंद मिला। काफी गेट खटखटाने के बाद भी कोई जबाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से धक्का देकर गेट खोलने पर कमरे में भारती फंदे से लटकती मिली।

- विवाहिता तीन साल पहले उसने लव-मैरिज की थी,मृतका के परिवार की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया है

आत्महत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद फंदे से शव को नीचे उतारा। पुलिस ने शव को कांवेटीया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इधर मृतक भारती की मां राजबाला ने दामाद आकाश सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया है कि आकाश सिंह नशे का आदी था। आए दिन वह भारती से मारपीट भी करता था। नशे में घर आकर आकाश के मारपीट और रुपये की मांग के बारे में भारती ने कई बार फोन कर बताया था। मृतका आत्महत्या ने से पहले भारती ने इमोशन स्टोरी इंस्टाग्राम पर लगाई थी।अगले दिन सुबह भारती की मौत की सूचना मिली थी। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा की

जयपुर । शासन सचिवालय में मंगलवार को अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रीगण समिति की द्वितीय बैठक आयोजित की गयी। बैठक में संसदीय

- बैठक में देवनारायण योजना की प्रगति, भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं की समीक्षा की

कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदन ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर बनी समिति की बैठक में देवनारायण योजना की प्रगति, रोस्टर



बैठक में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेदन ने भाग लिया।

एवं विभिन्न भर्तियों में आरक्षण, आन्दोलन प्रभावितों को अनुकम्पा नियुक्ति, 5 प्रतिशत अति पिछड़ा आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल कराने सहित समस्त बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। समिति ने कार्मिक विभाग को सकारात्मक रूप से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करने के पर विचार किया गया। साथ ही गुर्जर आरक्षण समिति द्वारा पिछली बैठक में सुझाएँ सातों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आगामी बैठक में सभी बिंदुओं के फैन्चुअल रिपोर्ट मंगवाने और उन

पर चर्चा करने निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग भास्कर ए. सावंत, प्रमुख शासन सचिव चक्रित्सा गायत्री ए. राठौड़, शासन सचिव, कार्मिक विभाग डॉ. कृष्णा कान्त पाठक, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल, निदेशक न्याय एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आशीष मोदी सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अजमेर के केकड़ी में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया। इस अवसर उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी दी।

मुख्यमंत्री ने केकड़ी में 1 हजार करोड़ के कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास किया

उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया

- **मुख्यमंत्री भजनलाल ने महीने में एक दिन ग्राम स्तर पर शिविर लगाने की घोषणा की, जिसमें आमजन के विभिन्न कार्य स्थानीय स्तर पर हो सकेंगे।**

उन्होंने कहा कि हम देश में अपनी तरह की पहली, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू कर 10 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों की गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर महीने में एक दिन शिविर लगाएगी, जिसमें आमजन के विभिन्न कार्य स्थानीय स्तर पर ही हो सकेंगे।

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ रु. से अधिक की महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं की हैं, जो इस क्षेत्र को

विकास के नए शिखर पर ले जाएंगी। मुख्यमंत्री ने केकड़ी में लगभग 423 करोड़ रुपये से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी-सरवाड़ क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का शिलान्यास किया। केकड़ी विधानसभा के 157 गांवों को शुद्ध पेयजल के लिए 300 करोड़ रुपये के अर्निश्चितकालीन निष्क्रियता को अनुमति देती है, वह विधायी प्रक्रिया और जन-इच्छा को बाधित करेगी।"

15 मई, 2025 को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा दायर संदर्भ में अप्रैल 8 के निर्णय से उत्पन्न हुए 14 संवैधानिक प्रश्नों को चिन्हित किया गया।

इनमें प्रमुख सवाल थे: क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए समयबद्ध आदेश दे सकती है? क्या विलंब की स्थिति में संविधान में "स्वतः सहमति" की कोई अवधारणा है? क्या अनुच्छेद 200 और 201 की न्यायिक समीक्षा या आदेशों के लिए व्याख्या की जा सकती है? संदर्भ का कहना है कि संविधान न्यायपालिका को ऐसा कोई स्पष्ट अधिकार नहीं देता और अप्रैल 8 के निर्णय ने एक ऐसा ढांचा बना दिया जो कार्यपालिका के स्वविवेक के अधिकार में हस्तक्षेप करता है। मंगलवार की सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल (केरल की ओर से) और वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन (तमिलनाडु की ओर से) ने इस संदर्भ का विरोध किया और इसकी वैधता पर सवाल उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता विल्सन ने कहा कि राष्ट्रपति के संदर्भ में उठाए गए सभी 14 प्रश्नों का उत्तर सुप्रीम कोर्ट पहले ही विभिन्न निर्णयों में, विशेष रूप से 8 अप्रैल, 2025 के तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के मामले में दे चुका है।

केकड़ी तक वर्षा जल की ट्रांसमिशन मुख्य प्रणाली और इनटेक पर इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य का भी शिलान्यास किया। (विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाजी ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में राज्य सरकार द्वारा हरियाली राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री एक विजन बनाकर पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यहां रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने परिसर में पीपल का पौधा भी लगाया। समारोह में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

भाजपा सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है और उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा, जो मिलना चाहिए।

उन्होंने वरिष्ठ वकीलों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक डिनर मीटिंग में यह साफ-साफ कहा कि देश के मामलों को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, उससे वे संतुष्ट नहीं हैं। कहा जाता है कि जब उन्हें प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी मिली, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब सरकार ने उनका इस्तीफा सार्वजनिक नहीं किया, तो उन्होंने स्वयं रात 9:30 बजे अपने ट्विटर पर यह जानकारी साझा कर दी।

धनखड़ आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और उसकी सिफारिश पर ही उन्हें पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनाया गया था।

धनखड़ किसानों और वंचित वर्गों की आवाज उठाते थे, जो मोदी सरकार को पसंद नहीं आया।

कोटा में कोचिंग सेंटरों में छात्रों की आत्महत्याओं पर उनकी सख्त टिप्पणी और शिक्षा की इन दुकानों (कोचिंग सेंटरस) के काम करने के तरीके पर उनकी आलोचना से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला नाराज हो गए, जो खुद कोटा से हैं और माना जाता है कि वे खुद कई ऐसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं।

बताया गया है कि उन्होंने अपने गुरुसे की जानकारी केन्द्रीय गृहमंत्री को दे दी थी, जिससे धनखड़ के साथ एक और टकराव हो गया।

इस समय, प्रधानमंत्री का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी टकराव चल रहा है, तो क्या धनखड़ का मामला भी उसी का हिस्सा है? वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि ऐसे बहुत से सवाल बहुत हैं।

समय, जब मोदी के खेमे में चुनावी गणित और रियलपॉलिटिक निर्णय लेने में महती भूमिका निभाना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनी प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए जोशी को भाजपा के सर्वोच्च पद पर देखना चाहते हैं।

इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि धनखड़ का इस्तीफा सत्ता के एक बहुत बड़े मंथन की केवल एक सतही घटना है। चूँकि भाजपा और संघ, सत्ता के उत्तराधिकार, गठबंधन प्रबंधन और आंतरिक असहमति की जटिलताओं से जूझ रहे हैं, इसलिये आने वाले दिनों में और भी अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

इस समय, सभी की नजरें राज्यसभा के नए अध्यक्ष और भाजपा के अगले अध्यक्ष पर हैं, ये दोनों ही निर्णय भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आयेंगे।

धनखड़ का इस्तीफा मंजूर, नये उपराष्ट्रपति का चुनाव शीघ्र होगा

राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश चलायेंगे

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बीते दिन ही धनखड़ ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र भेजकर पद से इस्तीफे की बात कही थी। उन्होंने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। मंगलवार को राज्यसभा को जगदीप धनखड़ के तत्काल प्रभाव से इस्तीफे के संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना (दिनांक 22 जुलाई) के बारे में सूचित किया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने लिखा, जगदीप धनखड़ को भारत के

उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उपराष्ट्रपति के पद छोड़ने के साथ

■ **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में जगदीप धनखड़ के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और उनकी प्रशंसा की।**

उपसभापति हरिवंश चलाएंगे। इसके अलावा, राष्ट्रपति की ओर से अधिकृत सदस्य को भी यह जिम्मेदारी दी सकती है।

उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जल्द से

जल्द कराना होगा। संविधान के अनुसार, मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य किसी कारण से उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराने का प्रावधान है।

कार्यकाल के दौरान इस्तीफा देने वाले धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। वीवी गिरि ने 20 जुलाई, 1969 और आर वेंकटरमन ने 24 जुलाई, 1987 को पद से इस्तीफा दिया था, दोनों ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए यह कदम उठाया था। जबकि पूर्व उपराष्ट्रपति कृष्णाकांत का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था।

199 करोड़ रु. के चंदे पर कांग्रेस को टैक्स देना ही होगा

नई दिल्ली, 22 जुलाई। कांग्रेस को पार्टी फंड में पड़े 199 करोड़ रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा। इसके लिए पार्टी को राहत नहीं मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या आईटीएटी ने आयकर रिटर्न देर से दाखिल करने और नकद दान सीमा के उल्लंघन के कारण पार्टी के छूट के दावे को खारिज कर दिया है।

क्या जगदीप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) याद दिला दें कि पिछले दिसंबर में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी, लेकिन यह इसलिए खारिज हो गया क्योंकि जयराम ने उनका नाम गलत लिखा और 14 दिन की पूर्व सूचना भी नहीं दी गई।

यह बात "मैच फिक्सिंग" का सबसे खुला उदाहरण मानी गई।

राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ को पक्षपाती माना गया - विपक्ष के लिए अनुचित, नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करने वाला, और सरकार का खुला समर्थन करने वाला। इसलिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं - अब सरकार ही उनके खिलाफ हो गई है। कहानी में नया मोड़ आ चुका है, और कहा जा रहा है कि अब कर्मा का फल मिल रहा है।

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के विधेयक को रोकें रखना) या "एक्सोल्सूट वोटो" (पूर्ण अस्वीकृति) की कोई अवधारणा नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई निष्क्रियता नहीं हो सकती, और जब भी कोई विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह संविधान के तहत उपलब्ध तीन विकल्पों में से किसी एक को अपनाने के लिए बाध्य है - या तो सहमति दें, या असहमति जताकर विधेयक पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटाएँ, या फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को रिजर्व करें।

अदालत ने आगे कहा कि यदि राज्यपाल असहमति जताते हैं, तो उन्हें अनुच्छेद 200 की पहली व्याख्या के अनुसार यथाशीघ्र विधेयक को संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटाना होगा।

इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए तीन महीने की समयसीमा तय

की। राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि वह पुनर्विचार के बाद विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक को अपनी सहमति दें। इस पर सहमति देने के लिए अदालत ने एक महीने की समयसीमा तय की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "अनुच्छेद 200 की कोई भी ऐसी व्याख्या, जो अर्निश्चितकालीन निष्क्रियता को अनुमति देती है, वह विधायी प्रक्रिया और जन-इच्छा को बाधित करेगी।"

इनमें प्रमुख सवाल थे: क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए समयबद्ध आदेश दे सकती है? क्या विलंब की स्थिति में संविधान में "स्वतः सहमति" की कोई अवधारणा है? क्या

ब्रिटिश नौसेना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तकनीकी खराबी के कारण यह उड़ान नहीं भर सका था। भारतीय वायुसेना ने भी विमान को जरूरी मदद मुहैया कराई। विमान में ईंधन भरा गया। इसके बावजूद यह उड़ान नहीं भर सका। आखिर में यूके रॉयल एअर फोर्स की एक टैक्नीकल टीम आई और हैरर में फाइटर जेट को ठीक करने का काम शुरू हुआ। एफ-35 की वापसी पर ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, "भारतीय एअरपोर्ट प्रशासन समेत पूरी टीम ने एफ-35 को ठीक करने में अहम योगदान दिया है। इस मदद के लिए ब्रिटेन हमेशा भारत का आभारी रहेगा।"

राजस्थान हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जा रहा है। संदीप तनेजा वर्तमान में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त हैं और जयपुर पीठ में राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। वहीं, बिपिन गुप्ता, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंधी भी जयपुर पीठ में नियमित वकालत करते हैं, जबकि बलजिन्दर सिंह व संजीत पुरोहित हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में प्रैक्टिस करते हैं। न्यायिक अधिकारी संगीता शर्मा फिलहाल अजमेर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर

कार्यरत हैं। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के काम की रफ्तार में काफी तेजी आएगी। फिलहाल हाईकोर्ट में करीब 6 लाख साठ हजार मुकदमों लंबित हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर साल 2025 बेहद अच्छा साबित हुआ है। हाईकोर्ट को इस साल अब तक करीब 15 जज मिल चुके हैं। जनवरी, 2025 में तीन, फरवरी माह में एक और मार्च माह में हाईकोर्ट जज के तौर पर चार नियुक्ति हो चुकी हैं। वैसे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 50 है।

क्या वरिष्ठ जेडीयू नेता हरिवंश सिंह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पर विचार किया जा रहा है। हरिवंश, एक पत्रकार से राजनेता बने धीरे-गंभीर व्यक्ति हैं, सभी दलों में उनकी अच्छी छवि है और उनका पदोन्नयन राज्यसभा में तनावों को कम करने में मदद कर सकता है।

एनडीए गठबंधन की दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए, भाजपा कथित तौर पर यह विचार कर रही है कि उपसभापति का पद तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) को दिया जाए। वर्ष 2019 में हुए कटु विभाजन के बाद, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के एनडीए में लौटने के साथ, भाजपा रणनीतिकार मानते हैं कि संसद में, टीडीपी जैसे किसी सहयोगी दल को सशक्त बनाने से गठबंधन की स्थिरता का संकेत मिल सकता है, जो बिहार चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हलचल केवल संसद

तक ही सीमित नहीं है। भाजपा के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर एक समानान्तर रस्साकशी चल रही है। जे.पी. नड्डा का बढ़ाया गया कार्यकाल जल्दी ही समाप्त हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निरंतरता और केन्द्रीयकृत नियंत्रण के पक्षधर माने जा रहे हैं। लेकिन आरएसएस इसका विरोध कर रहा है, वह पार्टी के इस शीर्ष पद के लिए अपनी सोच पर जोर दे रहा है।

इस संदर्भ में, संजय जोशी का नाम फिर से उभरकर सामने आया है, जो लंबे समय से आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता और एक समय भाजपा के प्रमुख संगठनकर्ता रहे हैं। मोदी ने एक दशक पहले आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जोशी को दरकिनार कर दिया था, लेकिन संघ अब भी उन्हें उच्च सम्मान देता है। जोशी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करके, संघ यह संकेत दे सकता है कि वह पार्टी का वैचारिक नियंत्रण फिर से हासिल करना चाहता है, खासकर ऐसे